

पुलिस प्रमुख की नियुक्तिके लिये नए नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के [पुलिस महानिदेशक \(DGP\)](#) की नियुक्तिके लिये नए नियम बनाए हैं।

मुख्य बिंदु

- उत्तर प्रदेश में DGP नियुक्तिके नए नियम इस प्रकार हैं:
 - यूपी कैबिनेट ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्तिनियमावली, 2024 को मंजूरी दे दी।
 - DGP का चयन अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड, अनुभव और शेष कार्यकाल पर विचार करते हुए एक समितिद्वारा किया जाएगा।
 - केवल वे अधिकारी ही इस पद के लिये पात्र हैं जिनकी सेवानिवृत्तसे पहले कम से कम छह महीने की सेवा शेष हो।
 - नियुक्त DGP न्यूनतम दो वर्ष तक पद पर रहेंगे।
 - चयन समितिमें एक सेवानिवृत्त [उच्च न्यायालय](#) के न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, [संघ लोक सेवा आयोग \(UPSC\)](#) के प्रतिनिधि और अन्य शामिल हैं।
- मौजूदा प्रथा:
 - राज्य सरकार को वर्तमान DGP की सेवानिवृत्तसे तीन महीने पहले UPSC को पात्र वरिष्ठ अधिकारियों की सूची भेजनी होगी।
 - UPSC सूची की समीक्षा करता है और अंतिम नियुक्तिके लिये तीन उम्मीदवारों की एक सूची राज्य को भेजता है।
 - रिक्ति सृजन की तिथिसे छह महीने का न्यूनतम कार्यकाल (सेवानिवृत्तसे पहले) वाले अधिकारी ही DGP के रूप में नियुक्तिके लिये पात्र होंगे। एक बार नियुक्त होने के पश्चात, DGP का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
- नये नियमों का कारण:
 - अस्थायी DGP की नियुक्तिको चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के बाद सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नोटिस के जवाब में ये नियम पेश किए गए थे।
 - याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि अस्थायी नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हैं, जिसका उद्देश्य पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से बचाना है।
 - यद्यपि 17 राज्यों ने अपने-अपने पुलिस अधिनियम बनाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अब तक ऐसा नहीं किया था।

Police Reforms in India



CONSTITUTIONAL STATUS

- Police and Public Order: State subjects (7th Schedule)



NEED FOR REFORM

- Colonial Law
- Custodial Death
- Lack of Accountability
- Political Interference
- Poor Gender Sensitivity
- Communal/Caste Bias
- No Anti-Torture Law



RELATED DATA

- Police-People Ratio: 153 police/100,000 people (Global benchmark: 222 police /100,000 people)
- Custodial Deaths: 175 in 2021-2022 (as per MHA)
- Women's Share: 10.5% of entire force (India Justice Report 2021)
- Infrastructure: 1 in 3 police stations is equipped with CCTV (India Justice Report 2021)



IMPORTANT COMMITTEES/COMMISSION



RELATED INITIATIVES

- SMART Policing (pan-India)
- Automated Multimodal Biometric Identification System (AMBIS) (Maharashtra)
- Real Time Visitor Monitoring System (uses AI and blockchain) (Andhra Pradesh)
- CyberDome (Tech R&D Centre) (Kerala)



CHALLENGES WITH POLICING

- Low Police-Population Ratio
- Political Superimposition
- Unsatisfactory Police-Public Relations
- Infra Deficit
- Corruption
- Understaffed/Overburdened

WAY FORWARD

- ↑ Police Budget, Resources
- ↑ Recruitment Process
- Implement Measures to Reduce Corruption
- ↑ Skills of Policemen
- Better Representation (Women, Minorities)

